(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बिहार राज्य में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या 9,484 है।

बिहार राज्य में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 22,397 है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जो मुख्यत: देश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डाक संबंधी कार्य करते हैं। ये कर्मचारी प्रतिदिन प्राय: 2 से 5 घंटे तक काम करते हैं। ये कर्मचारी जो भी कार्य करते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, इन्हें न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच भत्ते दिए जाते हैं। डाकघर भवनों को देय किराये का अतिरिक्त विभागीय पोस्ट मास्टरों को दिए जाने वाले भत्तों से कोई संबंध नहीं है।

**Power based Industries in Rural Areas**

2660. SHRI V. NARAYANASWAMY; Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government have been liberally allowing the co-operative sector power based industries in rural areas of the country to meet the demands of the rural population; and

(b) if so, what are the salient features of the said shceme and by when it will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.



**Anomaly in the payment of D.A. to Employees**

2661. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a difference between the dearness allowance paid to public sector employees and the Central Government employees; and

(b) if so, what action Government propose to take to remove the disparity which is causing unrest among the Public Sector Employees?

THE MINISTER OF INDUSTRY" (SHRr J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir.

(b) Government policy is that all public sector employees should be governed by the Industrial DA pattern. Government's directions to public sector employees to switch over to the Industrial DA pattern has been challenged in the Supreme Court. As per the direction of the Supreme Court a High Power Pay Committee has been constituted to go into the various aspects relating to pay scales and other incidental matters such as additional DA, interim relief and other allowances relating to employees working in the public sector governed by Central Government pattern pay scale and D.A.

**बिहार में डाक-तार सेवाएं**

2662. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मुंगेर जिले में डाक-तार सेवाओं के विकास में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) एस०टी०डी० आदि की सुविधाओं में कहां तक विस्तार किया गया ;

(ग) डाक-घरों की सुविधा में कहां तक विस्तार किया गया ;

(घ) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में डाक-तार सेवा की अपनी भूमिका के संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि देश के अन्य राज्यों में दी जा रही सुविधाओं के संबंध में बिहार बहुत पीछे है ; यदि हां, तो क्या इसका कारण बिहार सरकार है या केन्द्रीय सरकार है ?

**ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे)** : (क) **डाक सेवाएं** : चालू योजना वर्ष (1987–88) के दौरान मुंगेर जिले के लिए 6 नए डाकघर खोलने की मंजूरी प्रदान की गयी है । 1985–86 और 1986–87 के दौरान इस जिले में कोई डाकघर नहीं खोला गया ।

**तार सेवाएं** : मुंगेर जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गयी तार सेवाओं में हुई प्रगति इस प्रकार है :

(एक) मुंगेर जिले में एक स्वतंत्र विभागीय तारघर खोला गया है ।

(दो) 19 स्थानीय पी०सी०ओ० तथा 9 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेली-फोन-घर खोले गए हैं ।

(तीन) मुंगेर और पटना के बीच माइक्रोवेव संचार प्रणाली संस्था-पित की गयी है ।

(ख) पटना स्थित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के रास्ते 28–2–1987 से मुंगेर के लिए दोनो रास्ते से एस०टी०डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । मुंगेर के लिए एस०टी०डी० कोड 06344 है ।

(ग) 31–1–1988 को बिहार में कुल मिलाकर 10,897 डाकघर थे जिसमें मुंगेर जिले के 354 डाकघर शामिल हैं ।

(घ) **डाक सेवाएं** : सातवीं योजना (1985–1990) के दौरान देश में 6,000 नए डाकघर खोले जाएंगे और यह डाकघर मुख्यतया ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में खोले जाएंगे । इस विस्तार का लाभ बिहार सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मिलेगा ।

**तार सेवाएं** : सातवीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 600 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोले जाने की योजना है । सार्वजनिक टेलीफोन जो डाकघरों में खोले गए हैं वहां फोनो-काम आधार पर तार सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है ।

(ङ) **डाक सेवाएं** : जी नहीं । यह कहना सही नहीं कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य डाक सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है ।

**दूर संचार सेवाएं** : जी नहीं । 31–3–1987 की स्थिति के अनुसार 29.74 प्रतिशत षट्भुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गयी हैं । 6 अन्य राज्यों में ऐसे षट्भुजाकार क्षेत्रों की प्रतिशतता बिहार से कम है ।

इसके अतिरिक्त तार सेवाओं को अधुनातन बनाने संबंधी राष्ट्रीय योजना में बिहार भी शामिल है । और पटना में स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग तार प्रणाली की संस्थापना तथा बिहार राज्य में तार नेटवर्क में इलैक्ट्रॉनिक कुंजी पटल की व्यवस्था शामिल है । बिहार दूरसंचार के लिए 20 इलैक्ट्रानिक द्वि-लिपीय टेलीप्रिंटर सप्लाई किए गए हैं ।

**Exemption of custom duty on essential medicines**

2663. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have announced relief to the people by exempting essential medicines from custom duly;

(b) whether it is a fact that due to wrong implementation of measures by the Department the Objectivo of giving relief by the Government has been nullified;